



# गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

वर्ष : 16  
अंक : 039  
दि. 08.06.2026,  
सोमवार  
पाना : 04  
किंमत : 00.50 पैसा

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

## सम्मान, सुरक्षा, सुविधा



4+ करोड़ पीएम आवासों का निर्माण  
2014 के बाद से 25+ करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये



12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

गरीबों को 'सम्मान, सुरक्षा और सुविधा' देने वाले ये 12 वर्ष ही सच्चे अर्थों में 'विकसित भारत' की नींव हैं। - श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

# विपक्षी एकजुटता की नई परीक्षा, INDIA गठबंधन की बैठक से 2029 की रणनीति को मिल सकता है नया आकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती सक्रियता और आगामी चुनावी चुनौतियों के बीच सोमवार को आयोजित होने जा रही INDIA गठबंधन की बैठक को विपक्षी खेमे के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली के संविधान क्लब में होने वाली इस बैठक पर केवल विपक्षी दलों की ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा और राजनीतिक विश्लेषकों की भी पैनी नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों, राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों की दीर्घकालिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह बैठक विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। बैठक ऐसे समय आयोजित हो रही है जब विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक चुनौतियों, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल और विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भाजपा लगातार तीखे कार्यक्रमों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। ऐसे में INDIA गठबंधन की यह बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि विपक्षी एकजुटता की वास्तविक स्थिति का भी

परीक्षण मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में देश के 23 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहलू गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले और अन्य प्रमुख विपक्षी चेहरे इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख Mamata Banerjee की भूमिका को लेकर हो रही है। पिछले कुछ महीनों में विपक्षी राजनीति के भीतर नेतृत्व, रणनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की उपस्थिति और उनके विचारों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्ष को भविष्य में एक प्रभावी विपक्षी विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना है, तो क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच बेहतर तालमेल का आवश्यक होगा। इस संदर्भ में ममता बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक की एक विशेषता यह भी है कि



इसमें शामिल दलों के राजनीतिक हित और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाले दल, दक्षिण भारत में विभिन्न क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस—सभी का मानना है कि विपक्षी गठबंधन की है। इसके बावजूद इन दलों को एक मंच पर बनाए रखना INDIA गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कडगम (DMK) और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाले दल, दक्षिण भारत में विभिन्न क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस—सभी का मानना है कि विपक्षी गठबंधन की है। इसके बावजूद इन दलों को एक मंच पर बनाए रखना INDIA गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

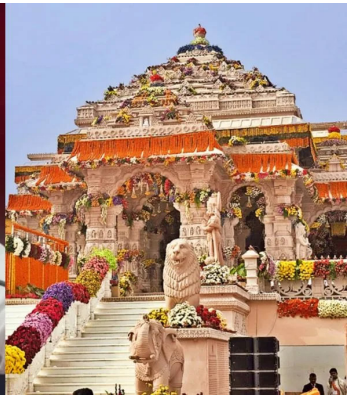
कांग्रेस महासचिव Jairam Ramesh ने बैठक से पहले कहा कि 23 दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। उनके अनुसार गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, संविधान की रक्षा और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर दबाव बढ़ा है और विपक्षी दलों की आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई,

बेरोजगारी, कृषि संकट, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों में राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहेंगे। इसी कारण बैठक में इन विषयों पर साझा रणनीति बनाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार संसद में विपक्षी दलों का कहना है कि INDIA गठबंधन के सामने केवल

सरकार की आलोचना करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उसे जनता के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि भी प्रस्तुत करनी होगी। विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने-अपने क्षेत्रीय हितों को संतुलित रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा संदेश देने में कितने सफल होते हैं। पिछले वर्षों में कई अवसरों पर विपक्षी एकता के प्रयास हुए, लेकिन चुनावी स्तर पर उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए इस बार रणनीति, संगठन और समन्वय को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बैठक में वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर प्रारंभिक विचार-विमर्श होने की भी संभावना है। यद्यपि चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दल दीर्घकालिक रणनीति बनाने लगे हैं। सीटों के तालमेल, संयुक्त प्रचार अभियान, साझा कार्यक्रमों और विभिन्न राज्यों में सहयोग के मांडल पर प्रारंभिक चर्चा हो सकती है। विपक्षी दल यह समझते हैं कि भाजपा जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के लिए उन्हें केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि लगातार समन्वय बनाकर चलना होगा। इस बैठक का एक और महत्वपूर्ण पहलू विपक्षी दलों के बीच विश्वास निर्माण है। कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और कुछ अन्य राज्यों में ऐसी स्थितियां पहले भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की एकता और राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना INDIA गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सोमवार की बैठक से कोई बड़ा चुनावी फार्मूला भले ही तत्काल सामने न आए, लेकिन यह निश्चित रूप से विपक्षी राजनीति के अगले चरण की दिशा तय कर सकती है। यदि बैठक में शामिल दल साझा मुद्दों पर एकजुटता दिखाने में सफल रहते हैं, तो यह विपक्ष के लिए सकारात्मक संदेश होगा। वहीं यदि मतभेद अधिक उभरकर सामने आते हैं, तो भाजपा को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। फिलहाल पूरे राजनीतिक परिदृश्य की नजर संविधान क्लब में होने वाली इस बैठक पर टिकी है। यह बैठक केवल वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में विपक्षी राजनीति के स्वरूप, नेतृत्व और रणनीति को आकार देने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जा रही है। 2029 की चुनावी लड़ाई भले अभी दूर हो, लेकिन उसके लिए राजनीतिक बिसात विद्यमान की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है और INDIA गठबंधन की यह बैठक उसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

## आस्था, पारदर्शिता और राजनीति के बीच घिरा राम मंदिर चढ़ावा विवाद

अयोध्या। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था अयोध्या से जुड़ी है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उसके प्रबंधन को लेकर उठे सवालोंने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दे दिया है। हाल के दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामले की जांच की मांग भी उठने लगी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने सोशल मीडिया मंच पर मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की जाने वाली राशि के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल वित्तीय मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने व्यापारिका से भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।



पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी पूरे प्रकरण की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोप निराधार हैं तो जांच के बाद सत्य सामने आ जाएगा और यदि कोई भी अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उनका कहना था कि आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान के संचालन में जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। इन आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा कि उन्हें भगवान श्रीराम और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को किसी प्रकार की शंका है तो जांच कराई जा सकती है और ट्रस्ट को उससे कोई आर्पित नहीं है। उनका कहना था कि जांच से सच सामने आएगा और यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता और मजबूत होगी।

अनियमितता सामने नहीं आएगी। विवाद के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी विस्तृत जानकारी देकर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था बहुस्तरीय निगरानी और ऑडिट प्रणाली के अंतर्गत संचालित होती है। उनके अनुसार मंदिर में प्राप्त होने वाले चढ़ावे का नियमित रूप से आंतरिक ऑडिट किया जाता है, जिसमें ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक अधिकारियों की भी भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। चंपत राय ने बताया कि वर्तमान समय में भी ऑडिट की प्रक्रिया जारी है और अब तक किसी प्रकार की उल्लेखनीय वित्तीय अनियमितता सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मंदिर जैसे बड़े धार्मिक संस्थान में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर जांच और सत्यापन की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रहे।

और उसे सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है। इसके बाद अगले कार्य दिवस में वह राशि बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। ट्रस्ट का दावा है कि चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित सभी विवरण समय-समय पर ट्रस्ट की बैठकों में प्रस्तुत किए जाते हैं। दिसंबर 2025 में आयोजित एक बैठक में भी चढ़ावे से जुड़े आंकड़ों और ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। ट्रस्ट का कहना है कि उसकी पूरी व्यवस्था लेखा-परीक्षा और वित्तीय अनुशासन के स्थापित मानकों के अनुरूप संचालित होती है। हालांकि राजनीतिक विवाद के कारण यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक या धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं रह गया है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। विपक्ष जहां पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहा है, वहीं ट्रस्ट और उसके समर्थक इसे राजनीतिक आरोपों का हिस्सा बता रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े विषयों का देश की राजनीति में विशेष महत्व रहा है, इसलिए इस तरह के मुद्दे स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा का विषय बन जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और सार्वजनिक लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाला दान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक होता है। इसलिए ऐसे संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। यदि किसी प्रकार के आरोप सामने आते हैं तो निष्पक्ष जांच न केवल विवादों को समाप्त करती है बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता को भी मजबूत बनाती है। फिलहाल इस मामले में किसी सरकारी एजेंसी या जांच संस्था द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि नहीं की गई है। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच वास्तविक स्थिति का पता किसी अधिकारिक जांच या प्रमाणिक रिपोर्ट के बाद ही चल सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि राम मंदिर से जुड़ा यह विवाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है।



क्या ममता का मैनेज लेकर प्रत्युक्त के चार गप वे मंगुली?

Garvi Gujarat हिन्दी

JioTV CHENNAI NO. 2002

Jio FIBER

Jio tv+

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिन्दी चैनल देखिये



# गुजरात स्थित विश्व की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का वैश्विक डंका 96 देशों के प्रतिनिधि प्राप्त कर रहे हैं विभिन्न जांच एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण

▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज्ञान के साथ एनएफएसयू का गौरवपूर्ण योगदान : अमेरिका तक पहुंची देश में निर्मित फॉरेंसिक उत्पाद; 17 राज्यों में 300+ मोबाइल वैन सेवाएं दे रही हैं

▶ अनुसंधान द्वारा शिक्षा के ध्येय के साथ एनएफएसयू ने स्थापित किए गए मापदंड : विमान दुर्घटना में डीएनए प्रोफाइलिंग से लेकर स्पोर्ट्स साइंस क्षेत्र में हासिल की विशिष्ट उपलब्धियां

▶ यूनिवर्सिटी के अब तक देश-विदेश में कुल 13 कैम्पस संचालित

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2009 में गांधीनगर में स्थापित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) ने मात्र 14 वर्षों की अल्प अवधि में अक्टूबर 2020 में 'इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस (आईएनआई)' का गौरवपूर्ण दर्जा प्राप्त किया है। संस्थापक कुलपति एवं भारत के वरिष्ठतम फॉरेंसिक वैज्ञानिक 'पद्मश्री' डॉ. जे.एम. व्यास के कुशल नेतृत्व में एनएफएसयू ने शिक्षा, अनुसंधान,

प्रशिक्षण और जांच के क्षेत्र में एक विशिष्ट शैक्षणिक मॉडल स्थापित किया है। वैश्विक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय कैम्पस एनएफएसयू गुजरात और भारत की ऐसी एक विशिष्ट सरकारी यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हुए युगांडा के जिंजा में अपना विदेशी कैम्पस स्थापित किया है। अब तक विश्व के 96 देशों के प्रतिनिधियों ने यहां से फॉरेंसिक साइंस का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। संस्था की शैक्षणिक उत्कृष्टता और ग्रीन कैम्पस से प्रभावित होकर विश्व के अनेक देशों ने अपने यहां एनएफएसयू का कैम्पस स्थापित करने के लिए



आधिकारिक प्रस्ताव भेजे हैं। निरंतर विस्तार कर रही इस यूनिवर्सिटी के मई 2026 तक देश-विदेश में कुल 13 परिसर हैं।

ग्राउंड लेवल जांच के लिए 300 से अधिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज और सटीक बनाने तथा न्यायालय में प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एनएफएसयू ने भारत में ही निर्मित अत्याधुनिक 'मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन' विकसित की है। यह वैन 24x7 प्रशिक्षित विशेषज्ञों और ग्रीन कैम्पस से प्रभावित होकर विश्व के अनेक देशों ने अपने यहां एनएफएसयू का कैम्पस स्थापित करने के लिए

300 से अधिक मोबाइल वैन कार्यरत हैं, जो न्याय प्रक्रिया को गति देने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं।

'स्टार्टअप क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार

एनएफएसयू ने अनुसंधान और स्टार्टअप को वेग देने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 'फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कार्डिसल' तथा एसएसआईपी के सहयोग से 'फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सेंटर' की स्थापना की है। यहां अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस केंद्र के माध्यम से 20 सित प्रदान करती हैं। देश के 17 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसी



आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर और यूरोप सहित कई देशों में नियात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्था ने भारत और अमेरिका दोनों में विशिष्ट पेटेंट स्वीकृतियां प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन और स्पोर्ट्स साइंस में मील का पत्थर साबित हुई उपलब्धियां

राष्ट्रीय आपदाओं और जटिल मामलों में भी एनएफएसयू अग्रणी रही है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के निकट हुई दुर्घटा एयर इंडिया फ्लाइट-171 विमान दुर्घटना में कुल 265 मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसयू की टीम ने अत्यंत तेज गति

से डीएनए प्रोफाइलिंग का भूगौरव कार्य पूरा किया था। इसके अतिरिक्त, खेल जगत में खिलाड़ियों के पोषण परीक्षण और प्रतिबंधित पदार्थों की पहचान के लिए यहां 'सेंट्रल ऑफ एक्सीलेस फॉर न्यूट्रिशनल टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्सपर्सन' (CoE-NSTIS) की स्थापना की गई है, जो देश में अपनी तरह का एक अनूठा वैज्ञानिक केंद्र है।

डीएनए फॉरेंसिक्स, ड्रॉन फॉरेंसिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय अनुसंधान कर रही इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता

## मातनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने घोला-जेटपुर-जैतलसर-उपलेटा-भायावदर-वांसजालिया सेक्शन का किया विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने दिनांक 06 जून, 2026 (शनिवार) को घोला जंक्शन स्टेशन से वांसजालिया जंक्शन स्टेशन तक विस्तृत विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घोला जंक्शन, जैतपुर, जैतलसर, उपलेटा, भायावदर एवं वांसजालिया स्टेशनों का संरक्षा, परिचालन एवं यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से गहन निरीक्षण किया।



अनुपालन तथा कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, मंडल रेल प्रबंधक ने सेक्शन में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों, पथ संरचना, सिग्नल एवं दूरसंचार व्यवस्थाओं तथा अन्य रेल अधोसंरचना

यात्री सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेल संचालन में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा संरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उच्च स्तर की सतर्कता, समन्वय और विशेष सतर्कता बरतने पर बल दिया। श्री वर्मा ने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं जैसे स्टेशन परिसर की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाएं तथा

संबंधी व्यवस्थाओं का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने रेल परिसरियों के रखरखाव एवं संरक्षा मानकों के प्रति विशेष सतर्कता बरतने पर बल दिया। श्री वर्मा ने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं जैसे स्टेशन परिसर की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाएं तथा

## अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस (ILCAD-2026) के अंतर्गत विशेष जनजागरण अभियान

रेलवे संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस (International Level Crossing Awareness Day - ILCAD-2026) के अवसर पर दिनांक 07 जून से 09 जून 2026 तक व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश "सुरक्षा प्रथम, हमेशा और हर जगह" (Safety First, Always and Everywhere) है।

मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी (Sr. DSO) श्री मानिक गुप्ता के निदेशन में सभी यातायात निरीक्षक (TI), सेक्शन कंट्रोलर (SC), वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (पथ) [SSE(P.



Way)], स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर (SS) तथा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख समपार फाटकों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के दौरान रेलवे अिधकारी एवं कर्मचारी आमजन, वाहन चालकों, स्कूली विद्यार्थियों तथा

विशाल जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनजागरूकता कार्यक्रमों में पंपलेट वितरण, सुरक्षा शपथ, जनसंवाद, उद्घोषणाएं तथा सुरक्षा संदेशों का प्रसार किया जाएगा। साथ ही रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 160 के अंतर्गत समपार फाटक से संबंधित नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होने तथा दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक के कारावास के प्रावधान की भी जानकारी दी जाएगी।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने आमजन से अपील किया है कि समपार फाटकों पर सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित रेल संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें। जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

# गुजरात के युवाओं को एआई से लेकर ईवी जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों का मिलेगा प्रशिक्षण: राज्य के आईटीआई में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम

▶ राज्यभर के आईटीआई में एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग, सोलर एनर्जी और 3डी प्रिंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए

▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में उभरते क्षेत्रों के लिए कुशल मानवबल तैयार करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

गांधीनगर : तकनीकी शिक्षा को उभरते औद्योगिक रक्षानों के अनुरूप बनाने के लिए गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कई 'न्यू एज' पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रोन फायलट, सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल), सूचना प्रौद्योगिकी, मेकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस सोलर सी मशीनिंग, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग तकनीशियन (3डी

प्रिंटिंग), तकनीशियन मेकैट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एडिड मैनुफैक्चरिंग (सीएमए प्रोग्रामर), आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट एप्लीकेशन), आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट सिटी) और स्मार्टफोन तकनीशियन-सह-रेपेरेटर जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा, "ये पाठ्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमेशन, स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे तेजी से



विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कुशल मानवबल तैयार करने के लिए शुरू किए गए हैं।

वहीं, श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिलाल अमृतिया ने कहा, "राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में इन न्यू-एज पाठ्यक्रमों

को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण प्रणाली को बदलती औद्योगिक जरूरतों के सुसंगत बनाए रखना है। इन पाठ्यक्रमों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गुजरात के सरकारी, अनुदानित और स्वचिंतपोषित आईटीआई में कुल 11 नए

पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, इस संदर्भ में प्रशिक्षणों के लिए 3312 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसके अंतर्गत, मेकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल) पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं, जबकि अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रम चुनिंदा आईटीआई में शुरू किए गए हैं। टेक्नोलॉजी-आधारित ये नए पाठ्यक्रम के कुल 73 आईटीआई में शुरू किए गए हैं, जिनमें से 67 सरकारी आईटीआई, 2 अनुदानित संस्थान और 4 स्वचिंतपोषित संस्थान शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं का कौशल बढ़ाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश में एक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में गुजरात में 12,729 ईवी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जबकि 2025 वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 7252 तक पहुंच गया था। वहीं, केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक (यानी डेटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), जो पूरी तरह से बिजली पर चलने वाले होते हैं) वाहनों का रजिस्ट्रेशन 111 फीसदी की वृद्धि के साथ 5271 यूनिट से बढ़कर 11,126 यूनिट तक पहुंच गया।

नए विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कुशल मानवबल तैयार करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक अधिकारी ने कहा, "गुजरात देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में गुजरात में 12,729 ईवी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जबकि 2025 वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 7252 तक पहुंच गया था। वहीं, केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक (यानी डेटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), जो पूरी तरह से बिजली पर चलने वाले होते हैं) वाहनों का रजिस्ट्रेशन 111 फीसदी की वृद्धि के साथ 5271 यूनिट से बढ़कर 11,126 यूनिट तक पहुंच गया।

पाठ्यक्रम शुरू होने से उद्योग के लिए कुशल मानवबल तैयार होगा। इसी प्रकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रशिक्षित ईवी तकनीशियन की मांग भी बढ़ेगी। इस वर्ष (2026) की शुरुआत में गुजरात के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2026 के दौरान राज्य में ईवी रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 75.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग, सरकारी प्रोत्साहनों और कर राहत जैसे कदमों के कारण संभव हुई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में गुजरात में 12,729 ईवी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जबकि 2025 वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 7252 तक पहुंच गया था। वहीं, केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक (यानी डेटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), जो पूरी तरह से बिजली पर चलने वाले होते हैं) वाहनों का रजिस्ट्रेशन 111 फीसदी की वृद्धि के साथ 5271 यूनिट से बढ़कर 11,126 यूनिट तक पहुंच गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की मांग भी बढ़ेगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए इवी मेकेनिक से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।" राज्यभर के विभिन्न आईटीआई में प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए 40 इलेक्ट्रिक वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

अभी गुजरात में 288 सरकारी आईटीआई हैं, जिनमें 177,912 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 100 अनुदानित आईटीआई में 16,200 सीटें और 171 स्वचिंतपोषित आईटीआई में 24,624 सीटें उपलब्ध हैं। गुजरात में कुल 560 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं, जिनमें कुल मिलाकर 2,18,736 सीटें उपलब्ध हैं। वर्तमान में गुजरात के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 138 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

## बावला स्टेशन यार्ड स्थित एलएचएस-62ए सार्वजनिक आवागमन हेतु अस्थायी रूप से बंद

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने जनसामान्य को सूचित किया है कि साबरमती-बोटदर रेलखंड के किमी 46/7-8 पर स्थित बावला स्टेशन यार्ड के एलएचएस क्रमांक 62ए (LHS-62A) को नगरपालिका बावला द्वारा किए जा रहे नाले (ड्रेन) निर्माण कार्य के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सभी प्रकार के सार्वजनिक आवागमन एवं वाहन परिचालन के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निर्माण कार्य को सुरक्षित, सुचारु एवं निबांध रूप से संपन्न कराने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निर्माण अवधि के दौरान कदम मार्ग से किसी भी प्रकार के दोपहिया, तिन्हिया, चारपहिया वाहन अथवा पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने



नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा कार्यस्थल पर प्रदर्शित यातायात एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं आवश्यक सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मार्ग को पुनः खोलने की सूचना पृथक से जारी की जाएगी।

रेल प्रशासन द्वारा जनसामान्य से अनुरोध किया जाता है कि वे बंदी अवधि के दौरान कदम स्थान पर किसी भी प्रकार का आवागमन न करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। भावनगर मंडल, पश्चिम रेलवे इस अस्थायी व्यवस्था से होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है तथा नागरिकों के सहयोग एवं समझदारी के लिए आभार प्रकट करता है।

## जनसेवा को समर्पित जीवन को अंतिम नमन, योगेशभाई पटेल की प्रार्थना सभा में उमड़ा जनसेवा

वडोदरा। मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्षों तक जनसेवा और विकास कार्यों को नई दिशा देने वाले वरिष्ठ विधायक योगेशभाई पटेल को रविवार को वडोदरा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नवलखी ग्राउंड में आयोजित उनकी प्रार्थना सभा में राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हजारों लोगों की उपस्थिति ने यह प्रमाणित कर दिया कि योगेशभाई पटेल केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता के बीच गहरी पैठ रखने वाले लोकप्रिय नेता थे। सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने दिवंगत नेता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके परिवारजनों को संतान दी। प्रार्थना सभा का वातावरण भावुकता और श्रद्धा से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवंगत योगेशभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोककाल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि योगेशभाई पटेल का निधन केवल उनके परिवार या निर्वाचन क्षेत्र की ही नहीं, बल्कि



पूरे गुजरात की अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने उनके सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव जनता के हितों को प्राथमिकता दी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक मुद्दों पर प्रभावी कार्य किया। यही कारण रहा कि उनके निधन की खबर के बाद विभिन्न वर्गों में शोक की लहर फैल गई थी। प्रार्थना सभा में उमड़ी भीड़ ने भी उनके प्रति लोगों के स्नेह और सम्मान को स्पष्ट

रूप से दर्शाया। सभा में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री भी उपस्थित रहे। मंत्री रमनभाई सोलंकी, मंत्री मनीषाबेन वकील, दंडक बालकृष्णभाई शुक्ला, विधायक केतन ईनामदार, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयदत्त सिंह परमार, पूर्व गृह मंत्री गोवर्धनभाई झडपिया तथा पूर्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा के दलों के नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत थी कि योगेशभाई पटेल ने राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों के बीच सम्मान अर्जित किया था। प्रार्थना सभा में सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक प्रतिनिधियों

और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी भाग लिया। उपस्थित लोगों ने दिवंगत नेता के साथ जुड़े अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा कि योगेशभाई पटेल हमेशा लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनने वाले नेता थे। आम नागरिकों के बीच उनकी सहज उपलब्धता और समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। सभा के दौरान कई वक्ताओं ने उनके

राजनीतिक और सामाजिक योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योगेशभाई पटेल ने अपने सार्वजनिक जीवन में विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उनके प्रयासों से मांजलपुर क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं को गति मिली और स्थानीय स्तर पर लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकीं।

**पश्चिम रेलवे - रतलाम इलेक्ट्रिक**

**ई-निविदा सूचना**

टेंडर नंबर Snt\_RTM\_26\_12\_Signal, दिनांक: 04.06.2026। 1) कार्य का नाम: निम्नलिखित कार्य के संबंध में एस एचटी टी सीएमपी को आर्गुटि स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग: - 1) गोधरा-नागदा खंड: सुरक्षा और विद्युतनिष्ठा में सुधार तथा दोषपूर्ण/पुराने सिग्नलिंग सिस्टमों का रिपेयरिंग और उपकरणों का प्रतिस्थापन। 2) आरडीएसएओ अनुमोदित अर्बिग सिस्टम द्वारा एसएचटी टी कार्य के महत्वपूर्ण उपकरणों के मौजूदा अर्बिग सिस्टम को बदलना, बदलना और मजबूत करना। 3) रतलाम डिवीजन: डिजिटल वीएचएफ सेट द्वारा फालोव 25-वाट वीएचएफ सेट का प्रतिस्थापन और उन्नयन। 2) कार्य की अनुमानित लागत: ₹. 10,83,98,569.82/- 3) ब्याज राशि: ₹. 21,68,000.00/- 4) निविदा खुलने का समय एवं दिनांक: दिनांक 30/06/2026 समय 15:30 बजे के बाद। 5) कार्य पूरा करने की अवधि: 12 माह। 6) निविदा अंतिम कार्यालय पत्तानी और थोली खोले का स्थान सीएमपी डीएस्टीई रतलाम, डीआरएम कार्यालय रतलाम म.प. निविदा सिर्फ अनलाइन E-निविदा पोर्टल [www.treps.gov.in](http://www.treps.gov.in) पर देखा व जमा किया जा सकता है।

हमें लाइक करें: [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

# मानसून से पहले सूरत की बड़ी तैयारी, खाड़ी बाढ़ और जलभराव पर स्थायी समाधान की दिशा में तेज हुए प्रयास

सूरत। हर वर्ष मानसून के दौरान जलभराव, खाड़ी में बढ़ते जलस्तर और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करने वाले सूरत शहर में इस बार प्रशासन ने समय रहते व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए सूरत महानगरपालिका ने प्री-मानसून अभियान को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाते हुए खाड़ियों, नालों और जल निकासी तंत्र की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है। प्रशासन का लक्ष्य केवल अस्थायी राहत देना नहीं, बल्कि उन समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना है जो वर्षों से शहर के कई इलाकों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

इसी क्रम में गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अक्षर की भौगोलिक संरचना, उन्होंने विशेष रूप से पुणा क्षेत्र स्थित सफाई अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को खाड़ी की वर्तमान स्थिति, सफाई कार्यों की प्रगति और मानसून के दौरान

## पंचायती राज मंत्रालय 9 जून 2026 को गांधीनगर गुजरात में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर आउटरीच कार्यशाला आयोजित करेगा

**यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें गुजरात भर की पात्र ग्राम पंचायतों और तालुका पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा**

भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय 9 जून 2026 को गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला में श्री विवेक भादड़ा , सचिव , पंचायती राज मंत्रालय , भारत सरकार ; श्रीमती मुक्ता शेखर , संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ; श्री धर्नजय द्विवेदी , प्रधान सचिव, पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग , गुजरात सरकार ; और डॉ. गौरव दहिया , अतिरिक्त विकास आयुक्त , गुजरात सरकार , राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड ( एचयूडीसीओ) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ( नाबाई ) के प्रतिनिधियों तथा पंचायतों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ भाग लेंगे।

यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी। गांधीनगर के आसपास की पात्र पंचायतों व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगी , जबकि इस दायरे से बाहर की पंचायतें अपने -अपने कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण में शामिल होंगी। इस पहल के माध्यम से , मंत्रालय का उद्देश्य गुजरात भर में ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत स्तर के नेताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करना और उन्हें आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना , उद्देश्य और परिचालन रूपरेखा से अवगत करना है। कार्यशाला के कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव द्वारा आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के दृष्टिकोण पर

## विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा,हरित पहल एवं जन-जागरूकता अभियान आयोजित

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने इस वर्ष की थीम “जलवायु परिवर्तन” पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर विषय पर्यावरण दिवस 2026 मनाया तथा पर्यावरणीय सततता एवं जलवायु संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अविषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता से वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। मंडल भर में कुल 60 पीपे लगाए गए, जिनका उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, जैव विविधता को प्रोत्साहित करना तथा कार्बन अवशोषण में योगदान देना है।

अभियान की प्रमुख विशेषताओं में से एक मुंबई सेंट्रल स्थित कोच केयर सेंटर के निकट अनुपयोगी भूमि का पुनर्विकास रहा। पूर्व में जहाँ टोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) संयंत्र स्थित था, उस क्षेत्र को एक सुंदर उद्यान के रूप में विकसित किया गया। यह उपलब्ध स्थान के प्रभावी उपयोग तथा शहरी हरितीकरण को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में विषय पर्यावरण दिवस अभियान के दौरान

आने वाली संभावित चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सूरत की भौगोलिक स्थिति और तीव्र शहरीकरण के कारण शहर के कई हिस्सों में बारिश के समय जलभराव की समस्या उत्पन्न होती रही है। विशेष रूप से निचले इलाकों और खाड़ियों से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से ही व्यापक रणनीति तैयार की है ताकि बारिश शुरू होने से पहले जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रफुल पानशेरिया के साथ सूरत की महापौर मायाबेन मावाणी, स्थायी जनप्रतिनिधि, नगरसेवक और नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में अक्षर की भौगोलिक संरचना, जल प्रवाह की दिशा, खाड़ियों में जमा होने वाली गाद तथा मानसून के दौरान जलस्तर बढ़ने की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि सफाई कार्य अधिक



प्रभावी और तेज गति से पूरा किया जा सके।

इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अत्याधुनिक ‘एम्पनीबियस एक्सकेवेटर’ मशीन का उपयोग है। यह विशेष मशीन पानी और जमीन दोनों स्थानों पर समान दक्षता के साथ कार्य कर सकती है। खाड़ियों में जमा प्लास्टिक

कचरा, झाड़ियाँ, गाद और अन्य अवरोधों को हटाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार खाड़ियों की जलधारण और जल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो रही है। वर्षों से जमा गाद और कचरे को हटाने से बारिश के दौरान पानी के बहाव

में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सकेगा। मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने निरीक्षण में जलभराव की घटनाएँ अधिक देखने को मिली हैं। प्रशासन का कहना है कि इन क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन लगाए जा रहे हैं और नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी संभावित समस्या

### मुंबई लोकल ट्रेन की महिला कोच में युवकों द्वारा गुंडागर्दी, महिलाओं की शिकायतों के बावजूद आरपीएफ-जीआरपी निष्क्रिय

(**छगनलाल मेवाड़ा द्वारा**) सूरत। जब देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में शनिवार को मुंबई की एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में एक युवक द्वारा की गई बदसलुकी की घटना से पता चलता है कि रेलवे पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी निष्क्रिय रही है। जब महिलाओं ने महिला डिब्बे में सवार युवक का विरोध किया और उसे डिब्बे

से उतरने को कहा, तो युवक चौंक गया और उसने मना कर दिया और महिला यात्रियों से अपद्र भाषा में बात की। एक युवक का महिलाओं से बहस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में महिलाएं उसे कोच से उतरने के लिए कहती सुनाई दे रही हैं। वीडियो में महिलाएं पहले युवक से लंडेज कोच से उतरने के लिए कहती हैं क्योंकि वह उसमें चढ़ चुका

से उतरने को कहा, तो युवक चौंक गया और उसने मना कर दिया और महिला यात्रियों से अपद्र भाषा में बात की।

एक युवक का महिलाओं से बहस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में महिलाएं उसे कोच से उतरने के लिए कहती सुनाई दे रही हैं। वीडियो में महिलाएं पहले युवक से लंडेज कोच से उतरने के लिए कहती हैं क्योंकि वह उसमें चढ़ चुका है। हालांकि, युवक इससे नाराज होकर कहता है कि महिलाएं जो चाहे करें, मैं नहीं उतररूंगा और खार स्टेशन पर उतर जाऊंगा। महिलाओं ने युवक को बताया कि ट्रेन खार स्टेशन से आगे निकल चुकी है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जा रही है, लेकिन युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अंततः, बांद्रा स्टेशन पर महिलाओं के

अध्ययन से पता चला : सस्ती जेनेरिक दवाएं महंगी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही प्रभावी और

(**छगनलाल मेवाड़ा द्वारा**) सूरत। केरल स्थित शोध संस्थान “फ्रेंड्स इन फार्माकोलॉजी” द्वारा डॉ. एबी फिलिप्स के नेतृत्व में और सात अन्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा एक अध्ययन किया गया। डॉ. फिलिप्स केरल के कोच्चि स्थित राजगिरी अस्पताल से जुड़े हैं और सोशल मीडिया पर “लिवर डॉक्टर” के नाम से मशहूर हैं। क्या सस्ती जेनेरिक दवाएं वाकई महंगी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार होती हैं?

यह एक ऐसा सवाल है जिसने न केवल मरीजों को बल्कि कई डॉक्टरों को भी अंधेरे समय से परेशान किया है। आम धारणा यह है कि कम कराने के लिए नाबाई और एचयूडीको के साथ साझेदारी की है। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ( आरजीएसए) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वायत्त , आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायतों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है , जिनमें से प्रत्येक यह प्रदर्शित करेगी कि आर्थिक स्वतंत्रता और सुशासन साथ - साथ चलते हैं। मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुसार , आत्मनिर्भर पंचायतें आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत नींव हैं। गांधीनगर कार्यशाला गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम के विस्तार की शुरुआत का प्रतीक है।

इस अध्ययन में केरल के विभिन्न क्षेत्रों से आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 22 दवाओं के 131 नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों में हृदय रोग, मधुमेह, संक्रमण, दर्द, एसिडिटी और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं। ये नमूने सात अलग-अलग प्रकार के

### लापरवाही ने ली चार जिंदगियां, जहरीली गैस से भरे ETP टैंक में उतरते गए कर्मचारी और मौत का शिकार बनते गए

सूरत। औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी किस तरह कुछ ही मिनटों में चार परिवारों की खुशियां छीन सकती है, इसका दर्दनाक उदाहरण रविवार को सूरत के वराछा खांड बाजार क्षेत्र में देखने को मिला। एक औद्योगिक इकाई के भूमिगत ईटीपी (एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट) टैंक की सफाई के दौरान चार सफाईकर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जहरीली गैस से भरे टैंक में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के प्रवेश किया गया था, जिसके कारण एक के बाद एक चार कर्मचारी मौत के मुंह में समाते चले गए। इस घटना ने न केवल पूरे शहर को झकझोर दिया है, बल्कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं।

हादसा रविवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे के आसपास वराछा क्षेत्र स्थित रतिह ज्वैलंस परिसर में हुआ। यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड ईटीपी टैंक की नियमित सफाई का कार्य किया जा रहा था। प्रारंभिक जांचकारी को अनुसार सफाई के लिए सबसे पहले कर्मचारी योगेश नानाभाई जादव टैंक के भीतर उतरे थे। कुछ ही क्षणों बाद उनका संपर्क बाहर होकर टैंक के अंदर गिर पड़े। बाहर मौजूद सहकर्मियों ने जब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो उन्हें बचाने के लिए विकास कुमार संतोषभाई सोनावने और विजय भीखाभाई अहिरे बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतर गए। दुर्भाग्यवश वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और कुछ ही समय में बेहोश हो गए।

दिया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक विभाग को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बारिश के समय जलभराव केवल आवागमन की समस्या नहीं पैदा करता, बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। गंदा पानी जमा होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जबकि दुर्गंध और प्रदूषण के कारण नागरिकों अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते नालों, खाड़ियों और ड्रेनेज नेटवर्क की सफाई बेहद आवश्यक है।

सूरत महानगरपालिका ने इस वर्ष शहर के कुछ क्षेत्रों को विशेष निगरानी वाले ‘हॉटस्पॉट’ के रूप में चिन्हित किया है। इनमें वराछा, पुणा, लिंबायत और उधना जैसे इलाके प्रमुख हैं, जहां अतीत में जलभराव की घटनाएं अधिक देखने को मिली हैं। प्रशासन का कहना है कि इन क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन लगाए जा रहे हैं और नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी संभावित समस्या

है। हालांकि, युवक इससे नाराज होकर कहता है कि महिलाएं जो चाहे करें, मैं नहीं उतररूंगा और खार स्टेशन पर उतर जाऊंगा।

महिलाओं ने युवक को बताया कि ट्रेन खार स्टेशन से आगे निकल चुकी है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जा रही है, लेकिन युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अंततः, बांद्रा स्टेशन पर महिलाओं के

### मिडिल ईस्ट संकट ने उड़ान उद्योग की बढ़ाई घिंता, मुनाफे पर गहराया दबाव

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष का असर अब केवल तेल बाजारों या वैश्विक व्यापार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका व्यापक अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। हवाई मार्गों की बढ़ती मांग के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों में उछाल और हवाई मार्गों में आ रही बाधाओं के कारण गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ईस्ट संकट ने विमानन क्षेत्र की आर्थिक गणनाओं को पूरी तरह बदल दिया है। संस्था के अनुसार, पहले जहां वर्ष 2026 में वैश्विक एयरलाइन उद्योग के संयुक्त शुद्ध लाभ का अनुमान लगभग 14 अरब डॉलर लगाया गया था, वहीं अब इसे घटकर लगभग 23 अरब डॉलर कर दिया गया है। यह कटीती दर्शाती है कि उद्योग की वित्तीय स्थिति पर युद्ध और अस्थिरता का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तुलना करें तो वर्ष 2025 में एयरलाइन उद्योग का अनुमानित लाभ 45 अरब डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई थी।

को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा नगर निगम ने मानसून के दौरान आयात स्थिति से निपटने के लिए भी व्यापक तैयारी की है। फ्लड कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जा रहा है, जबकि डी-वॉटरिंग पंपिंग स्टेशन की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता वाले पंप तैनात किए जा रहे हैं ताकि जलभराव की स्थिति में तेजी से पानी निकाला जा सके। साथ ही आपातकालीन राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

अधिकारियों के अनुसार तकनीकी उपकरणों, मशीनरी और मानव संसाधनों के बेहतर समन्वय के माध्यम से इस बार मानसून की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की योजना बनाई गई है। नगर निगम का दावा है कि समय रहते किए जा रहे इन प्रयासों से जलभराव की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी और खाड़ियों में बाढ़ जैसी स्थितियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

स्थायी नागरिकों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यदि खाड़ियों की नियमित सफाई और जल निकासी तंत्र का रखरखाव

डिब्बे में चढ़ने के बाद भी युवक ने किसी की बात नहीं सुनी और किंग्स सर्कल स्टेशन पर एक महिला को धक्का देकर भाग गया।

अगर आप 1512 हेल्पलाइन पर भरोसा करेंगे तो यह काम नहीं करेगा।

महिलाओं के डिब्बे में चढ़े उस “चक्कर आने” से परेशान युवक ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद नीचे नहीं उतरा, इसलिए महिलाओं ने रेलवे

लगातार किया जाए तो लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। कई नागरिकों ने उम्मीद जताई कि इस बार मानसून के दौरान उन्हें पिछले वर्षों जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सूरत महानगरपालिका का मानना है कि शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार और बदलते मौसमी पैटर्न को देखते हुए अब पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ आधुनिक तकनीक को अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है। इसी सोच के साथ प्रशासन ने इस वर्ष प्री-मानसून तैयारियों को केवल सफाई अभियान तक सीमित न रखकर एक समग्र बाढ़ प्रबंधन रणनीति के रूप में लागू किया है।

आगामी सप्ताहों में इन कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि समय पर किए गए इन प्रयासों के परिणाम मानसून के दौरान दिखाई देंगे और शहरवासियों को जलभराव, खाड़ी बाढ़ तथा उससे जुड़ी अन्य समस्याओं से काफी राहत मिल सकेगी। सूरत अब केवल मानसून की चुनौतियों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उनसे मुकाबले के लिए पहले से तैयार दिखाई दे रहा है।

### पुलिस बल ( जीआरपीएफ ) और सरकारी रेलवे पुलिस ( जीआरपी ) की हेल्पलाइन 1512 पर फोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगर महिलाओं के डिब्बे में सिर्फ दो या तीन महिलाएं ही सफर कर रही होंतीं , तो सोचिए वह युवक क्या करता ?

इस घटना से लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।

एयरलाइंस को अपने उड़ान कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा है, जिससे यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइंस का कुल ईंधन व्यय वर्ष 2025 के लगभग 252 अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि विमानन उद्योग के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ईंधन खर्च अब कुल परिचालन लागत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बन सकता है। ऐसी स्थिति में एयरलाइंस के लिए लाभ बनाए रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। इस संकट का असर यात्रियों की जेब पर भी पड़ने की संभावना है।

एयरलाइंस जब बंदी हुई लागत का सामना करती हैं तो उसका एक हिस्सा टिकट कीमतों के रूप में ग्राहकों पर स्थानांतरित किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में यूए और सुरक्षा तिंताओं के चलते कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं या उड़ानों के लिए एयरलाइंस को सीधा उड़ाने की अनुमति नहीं है। क्योंकि परिणामस्वरूप एयरलाइंस को वैकल्पिक और लंबे मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। लंबे मार्गों का सीधा असर परिचालन लागत पर पड़ता है। जिस विमान को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा चालक दल के कार्य घंटे, विमान रखरखाव और समय प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। कई

### के बाद प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को भी मिला

के डिविजनल फायर ऑफिसर रणजीतसिंह खडिया के अनुसार घटनास्थल के निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों ने पीपीई किट, सुरक्षा मास्क, गैस डिटेक्टर या अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने इसे प्रथम दृष्टया चेतावनी भी माना गंभीर लापरवाही बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे टैंकों में प्रवेश से पहले गैस स्तर की जांच, पर्याप्त वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि यह टैंक अजिल्हा प्रोसेसिंग यूनिट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह और उपचार के लिए उपयोग किया जाता था। निर्धारित सफाई के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य गैसों का पालन किया गया था नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री परिसर के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और विभिन्न कर्मचारियों तथा प्रबंधन के पृष्ठताछ शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईटीपी टैंकों में अक्सर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य